

संपादकीय

युवाओं को सशक्त बनाना

विकसित भारत / 2047 पहल का लक्ष्य 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह परिवर्तनकारी रोडमैप समावेशी विकास, सतत प्रगति और प्रभावी शासन पर जोर देता है। इसके केंद्र में भारत के युवाओं की सक्रिय भागीदारी है, जिन्हें इस बदलाव के प्रमुख चालक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, युवा शक्ति बदलाव का वाहक और लाभार्थी दोनों हैं। वॉयस ऑफ यूथ जैसे मंचों के माध्यम से, यह पहल युवा पीढ़ी की रचनात्मकता, ऊर्जा और विचारों को दिशा देने का प्रयास करती है, उनकी आकांक्षाओं को राष्ट्र के विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ती है और नवाचार, प्रगति और आत्मनिर्भरता के भविष्य को बढ़ावा देती है। 18 नवंबर को, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नए सिरे से राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की घोषणा की, जिसे अब विकसित भारत युवा नेता संवाद कहा जाता है। संवाद दो प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित होगा। पहला, राजनीति में नए युवा नेताओं को लाना, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को इन क्षेत्रों में शामिल करने के आव्यान का जवाब देना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य नेतृत्व क्षमता वाले युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, ताकि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष सीधे विकसित भारत के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। दूसरा, पारदर्शी और लोकतांत्रिक, योग्यता-आधारित चयन प्रणाली के माध्यम से विकसित भारत के लिए युवाओं का सार्थक योगदान सुनिश्चित करना। यह पहल भारत की प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विकसित भारत के लिए युवाओं को एकजुट करना विकसित भारत युवा नेता संवाद – राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 तीन प्रमुख श्रेणियों में युवा नेताओं के एक गतिशील समूह को एक साथ लाएगा। पहले समूह में हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत चुनौती के प्रतिभागी शामिल होंगे। दूसरे समूह में जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सवों से उत्तरोत्तर विभिन्न शासित औंगी तो विभिन्न विभागों को सेवानिवृत्ति के बाद भी बनाए रखा है। सत्ता में वापस आने के कुछ हफ्तों बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख तपन कुमार डेका का कार्यकाल बढ़ा दिया। इसके अलावा, सरकार ने अमित खरे और तरुण कपूर को भी पीएम के सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया, जिससे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में निरंतरता का एक ठोस संदेश गया, हालाँकि इस बार अन्य दलों के साथ गठबंधन में। 2017 से आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा को भी उनकी नियुक्ति के बाद से तीसरा विस्तार मिला। साफ है कि शीर्ष अधिकारियों को विस्तार देने की सरकार की प्रवृत्ति जारी है। वरिष्ठ आईएएस उत्पल कुमार सिंह, जो लोकसभा (सचिवालय) के मौजूदा महासचिव हैं, को कथित तौर पर एक और एक साल का विस्तार दिया गया है। श्री सिंह का कार्यकाल इसके महीने समाप्त होने की उम्मीद थी। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अध्यक्ष मल्लिका श्रीनिवासन को सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले ही सेवा विस्तार मिला, जिससे उन्हें नवंबर 2025

न कटेंगे न बटेंगे, यदि सिर्फ भारतीय रहेंगे

अतुल
बटेंगे तो कटेंगे इस सियासी
रे ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा
बाद महाराष्ट्र और झारखण्ड के
वाली माहौल में भी खूब सुर्खियां
पोरी हैं। साथ में पीएम मोदी का
पर्वक नारा एक हैं तो सेफ हैं शे
भी भारतीय राजनीति में अपनी
हाथ पकड़ी कर ली है, जिसे राहुल
धी अपने चिरपरिचित अंदाज में
जेपी की उपलब्धि बनाने पर तुले
हैं। एक बात तो साफ है कि
दोनों ही नारे सिर्फ चुनावों तक
सीमित नहीं रहने वाले हैं। इनका
लजयी बनना भी निश्चित है।
लों साल, चुनाव हों या न हो,
हो हो या आम इंसान, जुबान पर
नारे जरूर रहेंगे, और तब इनका
र अधिक सुनने को मिलेगा जब
जाति, धर्म की राजनीति की
। क्या हम कभी एक हो पाएंगे?
हम कभी सिर्फ एक भारतीय
रूप में पहचाने जाएंगे? क्या
ठाकुर, ब्राह्मण, अजा, अजजा
हिन्दू-मुसलमान के फेर से बाहर
कल पाएंगे? विश्वगुरु बनने का
सियासी ख्याब हमें दिखाया
है, क्या वह इसी बंटवारे के
ते पर चलकर पूरा होगा? ऐसे
ई अन्य सवाल हैं जिनका जवाब
ए अंदरूनी बंटवारे की मजबूत
डों के कारण शायद कभी न मिले।
ऐसा समय है जब भारत दुनिया

की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वहीं 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। वैशिक रूप से निखरती भारत की छवि, बढ़ता निवेश, और यहाँ की युवा शक्ति के बूते आज एक देश के रूप में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, और जापान, जर्मनी या अमेरिका जैसे देशों की बराबरी में आ कर खड़े हो गए हैं। लेकिन अफसोस कि एक भारतीय के रूप में हम एक नहीं हो पाए हैं। एक भारतीय के रूप में एकता न होने का दोष सिर्फ राजनीति को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजनीति तो लोगों को उन मामलों में भाग लेने से रोकने के लिए कहती है जो उनसे सीधे तौर पर संबंध रखते हैं। एक भारतीय के रूप में हमारी अखंडता हमारे अपने विवेक और देश व देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। राजनीति तो अपना योगदान पहले हिन्दू-मुस्लिम में देगी, फिर हिन्दू में भी जातियां बांटकर, ऊंच-नीच कर के देती रहेगी। हालांकि यह बात सिर्फ उन आम लोगों को ही समझने की जरूरत है जो राजनीतिक नारों के आवेश में

सोचने—समझने की शक्ति खो बैठते हैं। हम विश्व में अनेकता में एकता के लिए जाने जाते हैं। हालाँकि पिछले कुछ सालों में देश की इस छवि में धूंधलापन आया है। खुद को नागरिकों का हितैषी दर्शने के चक्रकर में राजनीतिक पार्टियां धर्म और बंटवारे की बातें अब भरे मंच पर गर्व से कहती नजर आती हैं। सोचने की जरूरत है कि यदि हम सब सिर्फ एक भारतीय के रूप में एक हो जाते हैं तो क्या कभी बटने, कटने या सेफ रहने का सवाल पैदा होगा?

क्या राजनेताओं को हिन्दुओं को हिन्दुओं में ही बांटने का स्वाद लेने का मौका मिलेगा? नहीं, जब लोग सिर्फ भारतीय बने रहने के लिए जागरूक होंगे तो न धर्म की लड़ाई बचेगी न ही जात-पात की और यह वह समय होगा जब हम सही मायने में वैश्विक लीडर बनने की राह पर होंगे। वो किसी ने कहा है न कि देश में एक मंदिर बनाने से क्या होगा, बनाना है तो पूरे देश को ही मंदिर बनाओ। फिर अंत में यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, हम घर में तो कमजोर रहेंगे ही साथ ही विदेशी ताकतें भी हम पर हावी होती रहेंगी। चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश इसका साक्षात् उदाहरण हैं।

के बीच

अजय

53 साल पहले आजादी मिलने के बाद पहली बार बांग्लादेश ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान से आने वाले जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दी। यह दो देशों के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क था, जो खून—खराबे और गहरे अविश्वास के इतिहास से जुड़ हुए हैं। मालवाहक जहाज, जो बांग्लादेश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कि परिधान निर्माण के लिए खाद्य पदार्थ और कच्चा माल लेकर आया था, कराची से चटगाँव के लिए रवाना हुआ। इससे पहले, पाकिस्तान के जहाजों को बांग्लादेश की यात्रा करने से पहले दूसरे देश में रुकना पड़ता था। इस समुद्री गलियारे की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ढाका में अंतरिम सरकार के तहत पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के दृष्टिकोण में बदलावों की श्रृंखला में नवीनतम है। श्री यूनुस ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाशिये पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और कहा था

ਬਾਈਰ-ਗਾਵਰਕਰ

१०

भारत में क्रिकेट प्रेमा आज से हो
है जल्दी उठना शुरू कर देंगे। ऐसा
लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत
बीच सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी और
पांच टेस्ट मैचों की सीरीज

बाड़ेर—गावस्कर ट्रॉफी आज से पथ में शुरू हो रही है। भारत उन दुर्लभ एशियाई टीमों में से एक है जिसने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए सफलता का स्वाद चखा है। भारत ने 2018–19 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया थाय उन्होंने

2020–21 में भी अपना सफलता का दोहराया। लेकिन इस भारतीय टीम के क्वांटों पर कई कमियाँ हैं। भारत को न्यूजीलैंड ने अपने घरेलू मैदान पर हरा दिया, जिससे टीम के बारे में कई असहज सवाल उठे। पहले टेस्ट में भी

भारत को टीम कमज़ार हांगा, क्योंकि
टेस्ट कप्तान रेहित शर्मा और गेंदबाज
मोहम्मद शमी एक या उससे ज्यादा
टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारत के कुछ
स्टार बल्लेबाज — खंघस तौर पर
विराट कोहली और केएल राहुल —

श्रीलंका की नई सरकार के लिए हनीमून वर्ष

लिल

भाई—भतीजावाद, भ्रष्टाचार और भयावह आर्थिक संकट से तंग आकर और अपने इतिहास में पहली बार, श्रीलंका के नागरिकों ने पिछले सप्ताह एक बड़े पैमाने पर अज्ञात राजनीतिक दल, नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) को अपने संसद में दो—तिहाई बहुमत से जीत दिलाई। यह आकस्मिक मतदान एनपीपी के नेता, मार्क्सवादी—लेनिनवादी—कम्युनिस्ट जनता विमुक्ति पेरामुना (जेगीपी) के अनुरा कुमारा दिसानायके के देश के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बुश्किल दो महीने बाद हुआ। हालांकि पिछले सप्ताह एनपीपी की संसदीय जीत कुछ हद तक पूर्वनुमानित थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ऐसी शानदार जीत की उम्मीद की थी। इसने शक्तिशाली राजपक्षे परिवार और अति प्रेमदासा, जो एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे भी हैं, जैसे राजनीतिक वंशों की हार सुनिश्चित की। यहां तक कि राजनीतिक दिग्गज रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के रूप में, पिछले दो वर्षों में कम से कम कर्ज में डूबे देश को सुधार के रास्ते पर ला खड़ा किया था, को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एनपीपी कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और डॉक्टरों का एक समूह अब 225 सदस्यीय संसद में 159 सीटों पर कब्जा करेगा। कई मायनों में, एनपीपी की जीत कोई साधारण जीत नहीं है। 22 मंत्रियों की एक छोटी सी कैबिनेट है। पिछली कैबिनेट में 50 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री थे। कुल 159 सांसदों में से 145 राजनीति में नए हैं और 20

महिलाएँ हैं। हालाँकि, सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि श्रीलंका के तमिल-हिन्दू बहुल उत्तरी प्रांत में एनपीपी ने कैसा प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति दिसानायके की जेवीपी का खूनी और उतार-चढ़ाव भरा अतीत रहा है। इसने दो विप्रोहार भड़काए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। जेवीपी ने श्रीलंका के तमिल-बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने के सभी प्रयासों को लगातार खारिज किया है, जैसे कि 1987 में भारत द्वारा लिखित श्रीलंकाई संविधान में 13वाँ संशोधन। लैकिन स्वायत्तता से जयादा, श्रीलंकाई तमिल दूसरे मुद्दों को लेकर नाराज हैं। विनाशकारी गृहयुद्ध की समाप्ति के 15 साल बाद भी, श्रीलंकाई सेना अपने प्रांतों में भूमि पर कब्जा करना जारी रखे

हुए है। स्थानीय पुलिस भी अभी भी कोलंबो में केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। चूंकि श्री दिसानायके ने सितंबर में राष्ट्रपति बनने से पहले तमिल मांगों का कोई संदर्भ नहीं दिया था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह के आकस्मिक चुनाव में भाग लेने वाले 690 दलों में से उनकी श्रट्टच्छ्वत्तमिल हृदयभूमि में दिल जीतने वाली आखिरी पार्टी होगी। और फिर भी, ठीक यही हुआ। जाफना में हाल ही में एक रैली में और अपने सुरक्षा दल की नाराजगी के बावजूद, श्री दिसानायके ने निडरता से तमिल दर्शकों के साथ घुलमिल गए और कब्जाई गई भूमि वापस करने का वादा किया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एनपीपी पारंपरिक रूप से कट्टरपंथी तमिल

गढ़ जाफना और वन्नी में जीतने वाली पहली सिंहली-बौद्ध पार्टी बन गई, जहां कभी आतंकवादी समूह, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का मुख्यालय हुआ करता था। जाफना के अर्थशास्त्री अहिलन कादिरगामर कहते हैं, घट्तर में एनपीपी की जीत ऐतिहासिक है। पिछले कुछ सालों में, तमिल नेशनल अलायंस (कोलंबो में संसदीय दल), जो वास्तव में अलगाववादी तमिल टाइगर्स का राजनीतिक मुख्पत्र था, ने कोई समाधान नहीं दिया। इसके बजाय, वे पश्चिमी अभिनेताओं की पैरवी करते रहे और तमिल प्रवासी टीएनए को सहारा देने के लिए उसमें पैसा डालते रहे। अलगाव बढ़ता गया। लोग नाराज थे, उनका विश्वास खत्म हो गया। और वे दिसानायके की ओर मुड़े। कोलंबो

की राष्ट्रीय शांति परिषद (एनपीसी) के निदेशक, जेहान परेरा, उत्तर में एनपीपी की अभूतपूर्व जीत के लिए अन्य कारकों की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, प्समिलों ने एनपीपी को घोट दिया क्योंकि वे देखते हैं कि देश के बाकी लोग इससे कितने खुश हैं, और उन्हें लगा कि वे भी इस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि एनपीपी को अब उस विश्वास का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। जई सरकार के पास बहुमत है, लेकिन उसे एकतरफा काम नहीं करना चाहिए। अब संसद में उसके अपने अल्पसंख्यक तमिल और मुस्लिम हैं। और चूंकि ये सांसद खुद जेवीपीए एनपीपी के जनादेश के तहत आए हैं, इसलिए उनके लिए सरकार को बाधित करना कठिन होगा। श्रीलंका

के सिंहली बहुसंख्यकों के लिए अपने अल्पसंख्यकों की तरह सोचना बहुत कठिन है।

जिसे मिटाया नहीं जा सकता है।
तो जब अन्य विफल हो गए हैं, तो
श्री दिसानायक की बड़े पैमाने पर
अनुभवहीन सरकार कैसे सफल
होगी? डॉ परेरा कहते हैं, ऐसे सहमत
नहीं कि भारतीय सरकार एक समझौता

लेकिन पिछले जेवीपी नेताओं ने एक सर्वी गुण का प्रदर्शन सादगी से कपड़े पहनते बाटी जीवन नहीं जीते। सा है कि जेवीपी समूह द्वांत एनपीपी और पूरे समाज में व्याप्त होंगे। नता है कि इस सरकार अस्थिति विरासत में मिली हैं अपने काम के लिए गा। सुधारों को छोड़

